कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती: एक प्रश्न

लेखक- उदित मिश्रा (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

01 अक्टूबर, 2019

"कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती सबसे बड़ा बदलाव रहा है; सेस (उपकर) और सरचार्ज को मिलाकर रेट में लगभग 35% से 25% की कमी आई है तथा सेस और सरचार्ज के बिना यह लगभग 30% से 22% रह गया है।"

पिछले हफ्ते ब्लूमबर्ग वैश्विक व्यापार मंच पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक निवेशकों के भारत आने से पहले उनके लिए एक मजबूत मार्ग प्रशस्त किया है। भारत में सरकार ने आर्थिक विकास में मंदी की मार से निपटने के लिए कई सुधारों की शुरुआत की है।

इन सुधारों की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव कॉर्पोरेट टैक्स दर में कटौती रहा है; साथ ही, सेस और सरचार्ज को मिलाकर रेट में लगभग 35% से 25% की कमी आई है तथा सेस और सरचार्ज के बिना यह लगभग 30% से 22% रह गया है। सरकार ने व्यवसायों को नए ऋण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी बैंकों को भी प्रेरित किया है तथा मौद्रिक नीति संचरण में सुधार और ब्याज दरों को कम करके ऐसे ऋणों की लागत को नीचे लाने के लिए आरबीआई के साथ काम कर रही है।

नीतिगत दृष्टिकोण से स्थिति 'धन रचनाकारों' को लाभ पहुंचाने के लिए ही होती है, जैसा कि पीएम ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में व्यवसाय उद्यमियों को संदर्भित करके कहा था।

सरकार ने टैक्स दरों में कटौती क्यों की है?

एक कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती काफी हद तक व्यवसायियों के लिए एक आयकर कटौती की तरह ही होती है। संक्षेप में, एक कम कॉर्पोरेट कर दर का मतलब है कि व्यवसाय में अधिक पैसा बचेगा; दूसरे शब्दों में, यह उनके मुनाफे को बढ़ाता है। चार्ट 1 और 2 के रूप में, पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की कॉर्पोरेट कर दरें काफी अधिक रही हैं। एक कम कर दर न केवल कॉर्पोरेट लाभप्रदता में सुधार करती है, बल्कि भारत को निवेश के लिए एक अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार भी बनाती है।

यह आर्थिक गतिविधि को कैसे प्रभावित करती है?

कटौती के तीन व्यापक प्रभाव हैं-

पहला, तत्काल अवधि में, यह अधिक धन के साथ कॉर्पोरेट्स को बढ़ावा देता है, जिसका उपयोग वे या तो मौजूदा फर्मों में पुनर्निवेश करने के लिए कर सकते हैं या नए उपक्रमों में निवेश करने के लिए सकते हैं। लेकिन यह भी संभव है कि वे इस धन का उपयोग पुराने ऋणों का भुगतान करने या अपने शेयरधारकों को उच्च लाभांश का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। कंपनियां निवेश करती हैं या नहीं, यह मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

CHART 1: EFFECTIVE TAX RATES HAVE COME DOWN SHARPLY

	Old effective tax rate	New effective tax rate
TURNOVER LESS THAN Rs 4,000 CR		
Taxable income less than Rs 1 cr	26	22.9
Taxable income more than Rs 1 cr	27.8	24.5
TURNOVER MORE THAN Rs 4,000 CR		
Taxable income less than Rs 1 cr	31.2	22.9
Taxable income more than Rs 1 cr but less than 10 cr	33.4	24.5
Taxable income more than Rs 10 cr	34.9	25.6

Source: Union Budget, PIB, Kotak Institutional Equities

CHART 2: NEW TAX RATE MORE IN LINE WITH NEIGHBOURHOOD

Source: Deloitte, KPMG, Kotak Economics Research

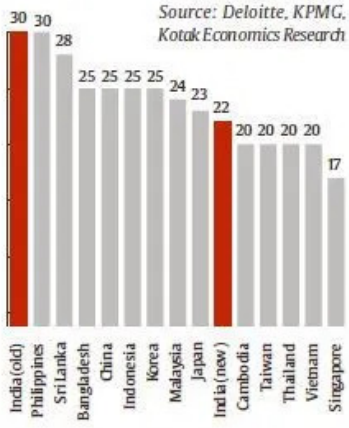

CHART 3: BANKING, FINANCIAL FIRMS GAIN THE MOST

Industry	Share in tax saving (in %)
Banking, Finance & Insurance	42.5
Iron & Steel	6.1
FMCG	6
Mining	5.7
Auto & Ancillary	5
Capital goods	4.3
Crude oil	3.8
Chemicals	3.1
Power	2.8
Infra	2.6

Source: AceEquity, CARE Ratings

किसी अर्थव्यवस्था में निवेश महत्वपूर्ण रूप से उपभोग स्तर पर निर्भर करता है। यदि उस क्षेत्र की फर्मों, जैसे - कार, की उपभोक्ता मांग उच्च है, तो वे खुशी-खुशी निवेश करेंगे - लेकिन अगर मांग नहीं है, तो उस क्षेत्र की फर्में निवेश नहीं करेंगी। हालाँकि, आय में कमी के कारण अगर खपत स्तर कम है और कंपनियों के पास बिना बिका हुआ स्टॉक (कारें और चॉकलेट इत्यादि) अधिक हैं, तो ताजा निवेश पर प्रभाव पड़ेगा।

दूसरा, मध्यम से दीर्घकालिक अवधि में, जो कि एक या दो और पांच साल या उससे अधिक हो सकता है, एक कॉर्पोरेट कर में कटौती से निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्पावधि में मांग में कमी के बावजूद, लंबी अवधि के मांग अनुमानों पर विचार करने के बाद निवेश के फैसले किए जाते हैं। अगर मांग बढ़ने की उम्मीद है तो निवेश बढ़ेगा और करों में कमी के साथ मुनाफा अधिक होगा। इन निवेशों से रोजगार भी पैदा होंगे और नियत समय में आमदनी भी बढ़ेगी।

हालांकि, एक कॉर्पोरेट टैक्स कटौती भी आर्थिक गतिविधि को इस हद तक कम कर देती है कि वह कर राजस्व के रूप में सरकार के हाथों में पैसे को कम कर देती है। अगर यह पैसा सरकार के पास होता, तो यह या तो वेतन देने या नई उत्पादक संपत्तियां बनाने में खर्च होता, जैसे कि सड़कें आदि या तो यह पैसा निवेशकों के बजाय सीधे उपभोक्ताओं के पास चला जाता।

तो क्या इस साल टैक्स में बढ़ोतरी से विकास होगा?

सच कहा जाये तो यह कहना मुश्किल है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। इस बात की भी संभावना अधिक है कि कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बावजूद भारत की जीडीपी वृद्धि चालू वित्त वर्ष में संघर्ष करती रहेगी और इसके कई कारण है।

पहला, आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख क्षेत्रों जैसे कि कृषि और विनिर्माण इत्यादि में श्रमिकों ने अपनी आय को निष्क्रिय होते हुए देखा है। देश में बेरोजगारी भी बढ़ी है। इसका साफ मतलब है कि लोगों की क्रय शक्ति गंभीर रूप से बाधित होगी और यही कारण है कि वे कम खरीद करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप कंपनियों के पास बिना बिके हुए स्टॉक की संख्या बढ़ती रहेगी।

दूसरा, केयर रेटिंग सूचकांक (चार्ट 3) द्वारा 2,377 कंपनियों के विश्लेषण के रूप में, कॉर्पोरेट टैक्स कटौती के परिणामस्वरूप टैक्स-बचत का 42% बैंकिंग, वित्तीय और बीमा क्षेत्रों की कंपनियों में जाएगा। ये फर्म दूसरों को सबसे अच्छा उधार दे सकती हैं लेकिन सीधे निवेश नहीं कर सकती, साथ ही विनिर्माण इकाइयां शुरू कर सकते हैं। इसलिए जब कर बचत उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगी, तो आर्थिक गतिविधियों में तत्काल वृद्धि नहीं हो सकती है। तालिका में अन्य क्षेत्र जैसे ऑटो और अनुषंगी, विद्युत, लौह एवं इस्पात उद्योग पहले से ही अधिक्षमता से जूझ रहे हैं और इस प्रकार निवेश की संभावना नहीं है।

क्या होता है राजकोषीय घाटा?

कटौती की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि कॉर्पोरेट कर कटौती से सरकार को राजस्व से 1.45 लाख करोड़ रुपये का घाटा होगा, जो जीडीपी का 0.7% है। यदि जीडीपी के 3.5% के बजट में राजकोषीय घाटे को जोड़ा जाए (जो सरकार के बाजार से उधार लेने का खाका है), तो यह प्रभाव राजकोषीय घाटे के 4.2% तक जाने के साथ काफी अधिक हो जायेगा।

लेकिन यहां भी, नकारात्मक प्रभाव उतना नहीं है जितना कि शुरू में मूल्यांकन किया गया था, यहां तक कि वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए खर्च में कटौती से इनकार किया है।

यह फैसला भी विभिन्न कारणों से लिया गया है। पहला, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कर की सीमा उतनी अधिक नहीं हो सकती है। दूसरा, कर का एक बड़ा हिस्सा लाभांश के माध्यम से सरकार को वापस आ जाएगा। तीसरा, जो भी कर का हिस्सा है, उसे केंद्र और राज्यों के बीच लगभग समान रूप से साझा किया जाएगा। इसके अलावा, आरबीआई पहले ही 58,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त लाभांश दे चुका है जो पहले बजट में नहीं था। अंत में, शेयर बाजारों में तेज वृद्धि और समग्र व्यापार भावना का मतलब होगा कि सरकार विनिवेश से अधिक कमाएगी।

नतीजा यह है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी के केवल 3.7% तक जाने की उम्मीद है।

कॉर्पोरेट टैक्स कटौती

चर्चा में क्यों?

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अन्य बातों के अलावा, कॉर्पोरेट कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की, इस प्रकार निगमों पर प्रभावी कर दर (विभिन्न उपकरों और अधिभार सहित) को 35% से 25% तक लाया गया।
- नई कॉर्पोरेट कर नीति के तहत, भारत में अक्टूबर से शुरू होने वाली और मार्च 2023 से पहले उत्पादन शुरू करने वाली नई कंपनियों पर 17% की प्रभावी दर से कर लगाया जाएगा।
- सरकार के निर्णय के बाद, निफ्टी और सेंसेक्स दोनों 5% से अधिक हो गए, जो एक दशक में सबसे बड़ी बढ़त है।
- **सरकार टैक्स क्यों काट रही है?**
  - कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आर्थिक वृद्धि में मंदी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो जून तिमाही में लगातार पांच तिमाहियों से गिरकर 5% हो गई है।
  - कर कटौती के पीछे सबसे तात्कालिक कारण नाराजगी हो सकती है जो विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ दिखाई है। उदाहरण के लिए, जुलाई में बजट के दौरान सरकार ने निवेशकों पर अतिरिक्त करों का बोझ डाल दिया था और देश से पैसा बाहर निकालना शुरू कर दिया था।
  - सरकार को उम्मीद है कि नई, कम कर दरें देश में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगी और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने में मदद करेंगी, जिसमें कमी देखी गई है।
- **इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा?**
  - कर कटौती, निजी क्षेत्र के हाथों में अधिक पैसा लगाकर, लोगों को अर्थव्यवस्था के उत्पादन और योगदान के लिए अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है। इस प्रकार वर्तमान कर कटौती व्यापक अर्थव्यवस्था को बढ़ने में मदद कर सकती है।
  - यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कॉर्पोरेट कर की दर, यह भी एक प्रमुख निर्धारक है कि कैसे निवेशक विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी आवंटित करते हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारों पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सबसे कम कर दरों की पेशकश करने का लगातार दबाव रहता है।
  - करों में वर्तमान कटौती भारत को पूर्वी एशिया में दरों की तुलना में भारतीय कॉर्पोरेट कर दरों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकती है। हालांकि, कर कटौती से सरकार को 1.45 लाख करोड़ रुपए का सालाना राजस्व नुकसान होने की आशंका है, जो अपने वित्तीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है।
  - उसी समय, यदि यह अर्थव्यवस्था को पर्याप्त रूप से पुनर्जीवित करने का प्रबंधन करता है, तो वर्तमान कर कटौती, कर संग्रह को बढ़ावा देने और राजस्व के नुकसान की भरपाई करने में मदद कर सकती है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. **कार्पोरेट कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

   1. यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है।
   2. आधार दर को 30% से घटा कर 25% कर दिया गया है।
   3. जबकि प्रभावी दर को 35% से घटाकर 22% कर दिया गया है।

   उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

   (a) केवल 1
   (b) 1 और 2
   (c) 2 और 3
   (d) उपरोक्त सभी

Expected Questions (Prelims Exams)

1. **Consider the following statements regarding Corporate Tax–**

   1. It is a type of direct tax levied on the profit of companies.
   2. The base rate has been reduced from 30% to 25%.
   3. The effective rate has been reduced from 35% to 22%.

   Which of the above statements is/are correct?

   (a) Only 1
   (b) 1 and 2
   (c) 2 and 3
   (d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: कॉर्पोरेट कर में हुई हालिया कमी किस प्रकार से भारत में विदेशी निवेश को सकारात्मक ढंग से प्रभावित कर सकती है? क्या इस कार्पोरेट कर की दर में कमी से भारतीय राजकोष पर कोई प्रभाव पड़ेगा? चर्चा कीजिए।

How the recent reduction in corporate tax can positively affect foreign investment in India? Will the reduction in this corporate tax rate affect the Indian revenue in any way? Discuss.

(250 Words)

नोट : 30 सितंबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (d) होगा।